



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2003/चैत्र 14, 1925

No. 326]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2003/CHAITRA 14, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2003

का.आ. 404(अ).—यतः, संसद ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक विधान अर्थात् आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15) बनाया है (यहां इसे पोटा कहा गया है) ताकि आतंकवाद को परिभाषित किया जा सके और उक्त अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न अपराधों के अभियोजन और दंड के लिए एक तीव्र कानूनी क्रियाविधि उपलब्ध कराई जा सके;

और यतः, पोटा में आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त उपबंध और प्रक्रिया संबंधी उपबंध मौजूद हैं और उक्त अधिनियम में साथ ही साथ निम्नलिखित प्रावधान करके यह सुनिश्चित किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ शक्तियों का दुरुपयोग न हो :—

- (i) कोई भी न्यायालय यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता;
- (ii) पुलिस उप-अधीक्षक से नीचे के रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध की जांच नहीं कर सकता;
- (iii) पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा अपने अपराध की स्वीकृति उक्त अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी बशर्ते कि यदि उस व्यक्ति को उसके इकबालिया बयान के साथ अड़तालीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है;
- (iv) पोटा में ऐसे किसी भी अधिकारी को दंड दिए जाने का उपबंध है जो विद्वेषपूर्वक या दुर्भावपूर्ण इरादे से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और इसमें ऐसे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का भी उपबंध है जिसके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अंतर्गत गलत तरीके से या विद्वेषपूर्वक प्रक्रिया से कार्यवाही की गई हो;

और यतः, समय-समय पर ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं कि पोटा के प्रावधानों का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जहां उसे लागू करने की विशिष्ट रूप से जरूरत महसूस नहीं होती है, इससे इस अधिनियम के दुरुपयोग की आशंकाओं को बल मिलता है।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने इन आशंकाओं और विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसकी सुविचारित राय है कि यह एक ऐसा विषय है जो पोटा की सांविधिक शक्तियों को लागू करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार को एक या अधिक पुनरीक्षा समितियां गठित करने हेतु सक्षम बनाता है;

अब, अतः, आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15), की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त एक पुनरीक्षा समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

- | | |
|---|-----------|
| (i) न्यायमूर्ति श्री अरुण बी. सहाय्या (सेवानिवृत्त), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | — अध्यक्ष |
| (ii) श्री एम. यू. रहमान, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, भारत सरकार | — सदस्य |
| (iii) श्री अरविन्द एस. इनामदार, आई. पी. एस. (सेवानिवृत्त), राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व सलाहकार | — सदस्य |

इस पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

- (i) यह पुनरीक्षा समिति विभिन्न राज्यों में उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोग के संबंध में व्यापक रूप से विचार करेगी और इसमें उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित किसी भी शिकायत को सुनने और तदनुसार, उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में कमी, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए अपने निष्कर्ष तथा सुझाव देने की शक्तियां निहित होंगी; और
- (ii) पुनरीक्षा समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी जिससे कि उक्त अधिनियम का प्रयोग केवल आतंकवाद से निपटने के लिए ही किया जा सके;

पुनरीक्षा समिति का कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फ़.सं. I-13013/3/2003-आईएस.-VII.]

एल. सी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2003

S.O. 404(E).—Whereas, Parliament has enacted a comprehensive legislation on the subject of terrorism titled the Prevention of Terrorism Act, 2002 (15 of 2002) (herein referred to as POTA) with the object of providing mechanism for punishment of various offences mentioned in the said Act;

And whereas, POTA contains both substantive as well as procedural provisions to effectively deal with terrorism and the said Act makes provisions for preventing misuse of the powers conferred by the said Act by *inter alia* providing as under :—

- (i) that no court can take cognizance of any offence under the said Act without the previous sanction of the Central Government or, as the case may be, of the State Government;
- (ii) that no police officer below the rank of the Deputy Superintendent of Police can investigate offences under the said Act;
- (iii) that no confession made by a person before a police officer lower in rank than a Superintendent of Police shall be admissible as evidence under the said Act and that the accused person is produced within forty-eight hours before a magistrate along with his confessional statement;
- (iv) that any officer who exercises powers maliciously or with mala fide intentions is punished and that compensation is awarded to a person who has been corruptly or maliciously proceeded against under the said Act;

And whereas, it has been alleged from time to time in certain quarters that the provisions of POTA are being applied in cases where they should not be invoked, thus giving rise to apprehensions regarding the said Act being misused.

And whereas, the Central Government has given careful consideration to aforesaid apprehensions and is of the considered opinion that the subject-matter warrants that the statutory powers conferred by POTA be invoked enabling the Central Government to constitute one or more Review Committees for the purposes of that Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the Prevention of Terrorism Act, 2002 (15 of 2002), the Central Government hereby constitutes a Review Committee, for the aforesaid purposes, consisting of the following persons with effect from the date of publication of this notification, namely:—

- | | |
|--|---------------|
| (i) Mr. Justice Arun B. Saharya (Retd.) Chief Justice
of High Court of Punjab and Haryana | — Chairperson |
| (ii) Shri M.U. Rehman, IAS (Retd.)
Former Secretary to the Government of India. | — Member |
| (iii) Shri Arvind S. Inamdar, IPS (Retd.)
Former Adviser to the Governor, Uttar Pradesh. | — Member |

The terms of reference of this Review Committee shall be as under :—

- (i) the Review Committee shall take a comprehensive view of the use of the said Act in various States and shall be empowered to entertain complaints or grievances with regard to enforcement of the said Act and accordingly, give its findings and suggestions for removing the shortcomings, if any, in the implementation of the said Act; and
- (ii) the Review Committee shall suggest measures to ensure that the provisions of the said Act are invoked for combating terrorism only.

The seat of the Review Committee shall be at New Delhi.

[F. No. I-13013/3/2003-IS-VII]

L. C. GOYAL, Jt. Secy.